SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बिहार में बेरोजगारी की समस्या एवं पलायन : नालन्दा जिले के विशेष संदर्भ में

आर. एस. जमुआर, Ph.D., पर्यवेक्षक, **राखी कुमारी,** शोधार्थी, स्नाकोत्तर अर्थशास्त्र विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोध गया, बिहार, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
आर. एस. जमुआर, Ph.D.
राखी कुमारी, शोधार्थी

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 17/01/2024
Revised on : -----
Accepted on : 18/03/2024
Plagiarism : 07% on 09/03/2024

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: **7%**
Date: Mar 9, 2024
Statistics: 217 words Plagiarized / 3303 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

शोध सार

प्राचीन काल से ही बिहार की अपनी गरिमा रही है। मानव के जन्म के पश्चात् उनके समक्ष तीन प्रमुख जरूरते होती है– वह है भोजन, वस्त्र और आवास। इन तीनों जरूरतों को पूरा करने के लिए अर्थतंत्र की आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर हाथों को काम मिलना चाहिए। आर्थिक विकास की मूल शर्त अर्थव्यवस्था में उपस्थित संसाधनों का सम्पूर्ण उपयोग है। संसाधनों में पूँजी एवं भूमि का स्थान सबसे ज्यादा सर्वोपरि है। अगर मानव पूँजी का सही तरीके से प्रयोग में लाया जाता है तो अर्थव्यवस्था में विद्यमान प्रत्येक श्रमबल को उनके श्रम के मुताबिक पारिश्रमिक मिल जाता है। जब मानव को रोजगार मिल जाता है तो इससे सिर्फ उसका ही विकास नहीं होता है, बल्कि इससे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। बेरोजगारी की समस्या अर्थव्यवस्था में उपस्थित कार्य करने को इच्छुक श्रमबल को बेकार कर देती है। यह समस्या मानव पूँजी को न केवल आर्थिक क्षति पहुँचाती है; बल्कि समाज के मध्य उन्हें मानसिक रूप से निरन्तर उत्पीड़ित करती रहती है। बेरोजगारी का प्रभाव उपभोग, व्यय, बचत करने की क्षमता एवं निवेश पर पड़ता है जो अर्थव्यवस्था में रूकावट और राष्ट्र के प्रगति के लिए घातक है। बेरोजगारी की स्थिति को समझने के लिए नालन्दा जिला का चयन किया गया है।

मुख्य शब्द

बेरोजगारी, आर्थिक संकट, कौशल, प्रशिक्षण, श्रम संगठन, मुद्रा स्फीति.

भूमिका

'बेरोजगारी' अर्न्तमन को झकझोर कर रख देने वाला शब्द है। वास्तव में यह एकमात्र शब्द नहीं बल्कि एक विकासशील देश की आत्मा को कमजोर बनाने वाला

सामाजिक अभिशाप है, जो तेजी से अपने अस्तित्व को मजबूती की ओर ले जा रहा है। अद्यतन आँकड़ो की ओर यदि ध्यान दिया जाय तो हम पाते हैं कि हमारा देश समृद्धशाली होने के बजाय बेरोजगारी की समस्या में उलझता जा रहा है। बेरोजगारी भारत की सम्पन्नता के मार्ग में उत्पन्न होने वाले व्यवधानों में प्रमुख रूप से चिन्तनीय है। हमारा देश मानव संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में सम्पूर्ण विश्व में दूसरे स्थान पर है, लेकिन मानव संसाधनों के पूर्ण उपयोग की कुशलता की कमी की अर्थव्यवस्था को क्षति पहुँचाती है। दूसरे शब्दों में बेरोजगारी मानव संसाधन की क्षति है, जो भारत के विश्व पटल पर विकसित राष्ट्र की भूमिका निभाने के मार्ग में पीछे की ओर ढ़केलता है। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप विश्व के अन्य उन्नत राष्ट्रों से बिल्कुल अलग है। विकसित राष्ट्र चक्रिय बेरोजगारी से ग्रसित है, यद्यपि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुपक्षीय परिदृश्य है, जो दिन–प्रतिदिन गंभीर रूप धारणा करता जा रहा है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति योग्यता होने एवं कार्य करने की इच्छा रखने के बाद भी स्वयं को रोजगार से वंचित पाता है, तो यह बेरोजगारी की भयावह स्थिति को प्रकट करता है। साधारण शब्दों में, बेरोजगारी का शाब्दिक अर्थ है, किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार के उत्पादक कार्य में नियोजित नहीं होना। भारत देश बेरोजगारी के अलग–अलग स्वरूपों से जूझ रहा है, जिनमें मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, औद्योगिक बेरोजगारी, शैक्षणिक बेरोजगारी प्रमुख रूप से देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। रोजगार संसाधन नहीं रहने की वजह से बिहार के लाखो लोग देश के अन्य प्रदेशों में पलायन कर चुके हैं और कुछ अन्य पड़ोसी देशों में शरण लेकर अपनी जीविका चला रहे हैं।

साहित्य समीक्षा

चौधरी डी. के. (2011) के अनुसार, बेरोजगारी की समस्या कई गंभीर समस्याओं जैसे गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, झुग्गी–झोपड़ी व अवैध बस्तियों के प्रसार, असमानता, अपराध, बालश्रम, भिक्षावृति आदि को उत्पन्न कर दिया है। बेरोजगारी को नौकरियों की मांग एवं इसकी आपूर्ति के बीच के अन्तर के रूप में माना जा सकता है। भारत में बेरोजगारी की उच्च दर जनसंख्या को तीव्र वृद्धि का प्रत्यक्ष परिणाम है। बिहार राज्य देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है, जिसने जून 2019 के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय राष्ट्रीय बेरोजगारी में भारी वृद्धि को दर्ज किया। वर्तमान शोध पत्र बिहार में बेरोजगारी की स्थिति से पीड़ित मुद्दों पर चर्चा करता है और उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए संभावित रणनीतिक हस्तक्षेतों द्वारा बेरोजगारी की बात करता है। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा कई नीतियाँ शुरू गई हैं और ग्रामीण कृषि समाज में मनरेगा, स्टार्ट अप इंडिया, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन आदि विशिष्ट रूप से विद्यमान है, फिर भी शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है।[1]

कुमार ए. एवं कुमार एम. (2020) ने बेरोजगारी की समस्या से उत्पन्न हुई पलायन की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए लेख प्रस्तुत किया है। बिहार से आजीविका की तलाश में पलायन कई दशकों से सामान्य हो गया है। पलायन के संदर्भ में बिहार राज्य शीर्ष स्थान पर है। बिहार में बेरोजगारी की दर देश के औसत से अधिक है। कम पैदावार, बढ़ती भूमिहीनता और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में कृषि अलाभकारी हो गई है। पलायन रोकने हेतु कृषि और गैर कृषि रोजगार उत्पन्न किया जाए। 2011 की गणना के अनुसार, 7.5 मिलियन प्रवासियों ने बिहार को एक मूल राज्य के रूप में बताया, जहाँ से उन्होंने पलायन किया। प्रवासियों की अधिकतम संख्या ने रोजगार की तलाश की प्रवास का कारण बताया। सबरीन एम. एवं बेहेरा डी. के. (2020) के अनुसार भारत में बिहार कम विकसित राज्यों में से एक रहा है, किंतु वर्तमान के वर्षों में एक प्रभावशाली विकास की बनावट दिख रही है। बिहार की आर्थिक संरचना बदल रही है, साथ–ही–साथ श्रम रोजगार की बनावट भी कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो रही है। 2004 और 2017–2018 के बीच कृषि में कार्यरत कर्मचारियों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से घटकर 40 प्रतिशत हो गई है, जबकि उद्योगों और सेवाओं में रोजगार की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्र, जो कृषि रोजगार का एक बड़ा हिस्सा है, ने भी गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि देखी है, हालाकि यहाँ बेरोजगारी की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। नवीनतम पीएलएफएस PLFS (2017–2018) डेटा सेट का उपयोग करते हुए, यह शोध–पत्र बिहार में विभाजन के बाद से संरचनात्मक परिवर्तन का एक व्यापक विश्लेषण

प्रदान करता है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बदलते रोजगार संरचना ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित है।[3]

चक्रवर्ती बी. (2019) के अनुसार, भारत में, देश की जनसंख्या का 54 प्रतिशत भाग 25 वर्ष से कम आयु वर्ग से है और छिपी हुई बेरोजगारी के उच्च दर का सामना कर रहा है। युवा रोजगार बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम लक्षित समूह ग्रामीण गरीब युवाओं तक पूरी तरह से पहुँचता है, किंतु 2 से 6 महीने बाद, कार्यक्रम का रोजगार प्रभाव शून्य हो जाता है। वेतन और उनके प्रवज्रित होकर रहने की लागत के बीच बेमेल होने के कारण मिला हुआ रोजगार भी छोड़ दिया जाता है।[4]

सिन्हा जे. के. (2019) द्वारा प्रस्तुत शोध–पत्र में 1990–2019 की अवधि में बिहार में समय श्रृंखला के आंकड़ों के आधार पर उत्पादन वृद्धि पर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के प्रभावों की जाँच की गई है। युवाओं की रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कौशल विकास के साथ बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में भौतिक पूँजी विस्तार और मानव पूँजी की संभावित उत्पादकता को बढ़ाना एवं आर्थिक विकास को सकारात्मक रुप से प्रभावित करना प्रमुख निर्धारक प्रतीत होता है।[5]

देशवाल ए. (2017) ने अपने लेख में 2004 से 2012 तक के आंकड़ों को आधार बनाया है। 2004–2005 से पहले की अवधि के रोजगार के पैटर्न को जोड़ने और उपभोग के क्षेत्र में सामने आए विकृत विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे पैटर्न का पता चलता है जो गरीबी में कमी की दरों के साथ सामंजस्य बिठाने में समस्या उत्पन्न करती है। भोजन पर प्रति व्यक्ति व्यय सभी वर्गों में घट रहा है और श्रम शक्ति अधिक से अधिक हाशिए पर जा रही है।[6]

श्रीनिवासन टी. एन. एवं ऐलन टी. (2013) द्वारा भारत में 1970 के शुरुआत से रोजगार एवं बेरोजगारी के रुझानों का विश्लेषण किया गया। यद्यपि रोजगार व बेरोजगारी के आकड़ों के कई स्त्रोत विद्यमान है किंतु समय के साथ सभी स्त्रोतों में रोजगार की स्थिति समान नहीं है। इसके अलावा, अधिकांश स्त्रोतों में जानकारी कुछ भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित है। NSO के राष्ट्रीय पंचवर्षीय घरेलू सर्वेक्षण में अनिवार्य रुप से रोजगार और बेरोजगारी की समान अवधारणाओं का उपयोग किया गया था। केरल और बिहार राज्य के अध्ययन के निष्कर्ष में बिहार की स्थिति बेहद परेशान करने वाली है। बिहार ने भारत के वैश्वीकरण से महत्वपूर्ण रुप से लाभ को प्राप्त नहीं किया है।[7]

वेंकटेश पी. (2013) ने अपने पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था के संक्रमण के संदर्भ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तीन विशेषताओं ग्रामीण रोजगार पैटर्न में बदलाव, ग्रामीण मजदूरी और कृषि विकास में रुझान एवं कृषि मजदूरी व उत्पादकता के बीच संबंध की जाँच की है। 2009–2010 में ग्रामीण गैर कृषि रोजगार क्षेत्र ने लगभग 38 प्रतिशत पुरुष और 21 प्रतिशत महिला श्रम बलों को रोजगार प्रदान किया। ग्रामीण गैर कृषि बेरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में निर्देशित नीतियाँ बेहतर मजदूरी दर प्रदान करेंगी।[8]

कश्यप के. (2005) के अनुसार बेरोजगारी और गरीबी का दुश्चक्र बिहार की अर्थव्यवस्था को घेर रहा है। गैर–कृषि व्यवसायों ने अभी तक अपनी बढ़ती जनसंख्या को अवशोषित नहीं किया है। उत्तर और मध्य बिहार में कई समस्याएँ हैं, जिनमें बाढ़, शिक्षा का निम्न स्तर प्रमुख है जिससे कि न तो बेरोजगारी कम हो रही है और न ही निर्धनता।[9]

भट्टाचार्य बी. (2000) के अनुसार, 'बिहार के विभाजन ने राज्य के भविष्य पर पहले से ही व्यापक चिंता को और बढ़ा दिया है। विभाजन ने बिहार के भविष्य के प्रश्न को ला खड़ा किया है। झारखंड एवं बिहार के विभाजन ने बिहार के विकास की वास्तविकता को प्रकट कर दिया है। भविष्य की समस्याओं में बेरोजगारी एवं आर्थिक संकट को प्रमुख रुप से सम्मिलित किया गया है।[10]

प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। द्वितीयक स्त्रोतों में गुगल, स्कॉलर, इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटिकल वीक्ली, एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्स, रिसर्च रिव्यू, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनोमिक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार के नीति एवं योजना आयोग द्वारा प्रकाशित आंकड़ों तथा टिप्पणी का उपयोग किया गया है। एम. एस. वर्ड का प्रयोग तालिका निर्माण हेतु किया गया है। प्रतिशत व अनुपात विधि से डेटा के विश्लेषण का कार्य पूर्ण हुआ है।

बेरोजगारी की संकल्पना का परिचय

बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है, जो उन व्यक्तियों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो रोजगार योग्य हैं और सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश भी कर रहे हैं, किंतु फिर भी रोजगार को प्राप्त कर पाने में असफल एवं असमर्थ है। इस समूह में वे सभी लोग सम्मिलित हैं, जो कार्यबल श्रेणी में तो आते हैं किंतु उनके पास उपयुक्त रोजगार नहीं है। बेरोजगारी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के संकेतकों में से एक के रुप में अपना कार्य करती है। शिक्षा का निम्न स्तर, विकलांगता तथा व्यक्तिगत मुद्दों से प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने हेतु रोजगारपरक नहीं माना जा सकता है। ऊपर उल्लिखित श्रेणी बेरोजगार लोगों की वास्तविक संख्या का प्रतिनिधित्व करती है।

श्रम सांख्यिकी ब्यूरो (बीएलएस) ने 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति, जिनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है, को बेरोजगार की श्रेणी में स्थान प्रदान किया है। इस श्रेणी के भीतर एक और श्रेणी आती है, जिसमें व्यक्ति द्वारा 12 महीने सक्रिय रुप से रोजगार की तलाश की जाती है, किंतु अंतिम के चार सप्ताह में रोजगार की तलाश छोड़ दी जाती है, इसे 'हतोत्साहित श्रमिक' कहा जाता है। (श्रम सांख्यिकी ब्यूरो 2022)।[11]

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार बेरोजगारी की स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का संबंध एक विशिष्ट समय एवं उम्र सीमा के भीतर कार्य के अभाव, कार्य का उचित पारिश्रमिक न मिलने अथवा स्वरोजगार के न होने से है । (अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2013)।[12]

एडमंड एस. फेल्प्स जो एक अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं नोबेल विजेता हैं, ने समष्टि आर्थिक नीतियों के विश्लेषण हेतु मुद्रास्फीति, मजदूरी एवं बेरोजगारी को विशेष रुप से प्रयुक्त किया तथा समष्टि आर्थिक नीतियों की व्याख्या की है। (एडमंड एस. फेल्प्स 2006)

प्रस्तुत शोध–पत्र का संदर्भ नालन्दा जिला है। नालंदा भारत में बिहार का जिला है। यह प्राचीन मगध का इलाका है। यहाँ की आम बोलचाल की भाषा मगही है। इसका मुख्यालय वर्तमान का बिहार शरीफ है। ऐसे यह क्षेत्र अपने प्राचीनतम इतिहास के लिए पुरे विश्व में लोकप्रिय है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ सुदुर देशों से छात्र अध्ययन के लिए भारत आते थे। इसका क्षेत्रफल 2,367 कि. मी. (914 वर्ग मील) है। यहाँ की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 2,872,523 है।

बिहार के लाखों लोग रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है। इसमें नालन्दा जिला भी एक है। इसका एकमात्र वजह रोजगार के अवसर का नगण्य होना। अगर यहाँ रोजगार के अवसर पैदा किये जाते तो शायद पालयन की गति पर रोक लग सकता है। बाहर जाने पर इन्हें अपमानित होना पड़ता है। नालन्दा जिले के राजू दानवीर जो हिलसा अनुमंडल के पत्रकार है। उन्होंने बताया कि बिहार जैसे राज्य के लिए पलायन प्रमुख समस्या है। जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ कल–कारखाने भी नहीं है जिससे बेरोजगारी में कमी आ सकती है। एकमात्र सिर्फ पर्यटक की दृष्टि से राजगीर को विकसित किया गया है। इससे क्षणिक लोगों को सिर्फ स्थानीय स्तर पर स्वयं का रोजगार मिला है। इन क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी को पलायन से रोकने के लिए अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन की आवश्यकता है।

आज बिहार और अन्य पडोसी राज्यों में रोजगार की कमी की वजह से पढ़े–लिखे लोगों के साथ अशिक्षित भी रोजगार के लिए अपने राज्य से पलायन कर विदेशों एवं देश के अन्य हिस्सों में जाने के मजबूर हैं। यह स्थिति पूरे देश में लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसके लिए जरूरत है इस बात की हैं कि बिहार में कल–कारखानों और अन्य रोजगार की योजना को बढ़ा दिया जाय ताकि एक खास आबादी के लोगों को अच्छे जीवन पालन करने का सुअवसर प्राप्त हो सके।

तालिका 1: भारत एवं बिहार में शहरी बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

क्षेत्र	1993–94	1999–2000	2004–05	2009–10	2011–12	2017–18	2018–19
बिहार	71	74	64	73	56	90	105
भारत	45	47	45	34	34	78	77

(स्त्रोतः नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे [PLFS], NSO)

बेरोजगारी की स्थिति शहरी क्षेत्र में विभिन्न समय में भिन्न–भिन्न आंकड़ों के रुप में प्रकट हुई है। 1993–94 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 71 व्यक्ति एवं भारत में 45 व्यक्ति बेरोजगार पाए गए । 1999–2000 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 74 व्यक्ति एवं भारत में 47 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2004–05 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 64 व्यक्ति एवं भारत में 45 व्यक्ति बेरोजगार थे, वहीं 2009–10 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 73 व्यक्ति एवं भारत में 34 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 56 व्यक्ति एवं भारत में 34 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2017–18 की समय अवधि में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 90 व्यक्ति एवं भारत में 78 व्यक्ति रोजगार के अभाव में जीवन यापन करने को विवश थे। 2018–19 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 105 व्यक्ति एवं भारत में 77 व्यक्ति बेरोजगार थे। भारत की तुलना में बिहार में बेरोजगारों की संख्या काफी अधिक है।

अन्य राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की तुलना में बिहार में बेरोजगारी की स्थिति एक गंभीर चिंता का विषय है। 2018 – 19 के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में बेरोजगारी का स्तर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि से कई गुना अधिक है। सभी राज्यों में से सबसे अधिक बेरोजगारी नागालैंड (211) में है तथा सबसे कम बेरोजगारी की अवस्था को प्राप्त राज्य गुजरात (32) है।[13]

तालिका 2: भारत एवं बिहार में ग्रामीण बेरोजगारी की दर (प्रति 1000)

क्षेत्र	1993–94	1999–2000	2004–05	2009–10	2011–12	2017–18	2018–19
बिहार	16	18	15	20	32	70	102
भारत	12	15	17	16	17	53	20

(स्त्रोतः एन एस ओ इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिर्पोट)

बेरोजगारी की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न समय में भिन्न–भिन्न आंकड़ों के रुप में स्पष्ट हुई है। 1993–94 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 16 व्यक्ति एवं भारत में 12 व्यक्ति बेरोजगार पाए गए। 1999–2000 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 18 व्यक्ति एवं भारत में 15 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2004–05 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 15 व्यक्ति एवं भारत में 17 व्यक्ति बेरोजगार थे वहीं 2009–10 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 20 व्यक्ति एवं भारत में 16 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2011–12 के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति्त पर 32 व्यक्ति एवं भारत में 17 व्यक्ति बेरोजगार थे। 2017–18 की समय अवधि में बिहार में प्रति 1000 व्यक्ति पर 70 व्यक्ति एवं भारत में 53 व्यक्ति रोजगार के अभाव में जीवन यापन करने को विवश थे। 2018–19 में प्रति 1000 व्यक्ति पर बिहार में 102 व्यक्ति एवं भारत में 50 व्यक्ति बेरोजगार थे। भारत की तुलना में बिहार में ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या दुगुनी से भी अधिक है।

बेरोजगारी की अवस्था के संदर्भ में यदि ग्राम एवं शहर के बीच तुलना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी की दर कम है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शहरी बेरोजगारी की दर ग्रामीण बेरोजगारी से अधिक है, किंतु ग्रामीण बेरोजगारी की दर का शहरी बेरोजगारी की तुलना में कम होने का कारण छिपी हुई बेरोजगारी भी हो सकती है, क्योंकि कुछ श्रमिक को यह भी ज्ञात नहीं होता है कि उनकी सीमान्त उत्पादकता शून्य है एवं वे छिपी हुई बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। इस परिस्थिति में यदि कार्य क्षेत्र से कुछ श्रमिकों को रोजगार से मुक्त भी कर दिया जाए तब भी उत्पादकता में कोई परिवर्तन नहीं होता है।[14]

बेरोजगारी का जीवन स्तर पर प्रभाव और पलायन

भारत देश के साथ–साथ बिहार में बेरोजगारी की समस्या अधिक है। इसका पहला कारण शिक्षा के प्रतिशत मे कमी का होना। सरकारी नीतियों की वजह से एक लम्बे समय तक युवा वर्ग रोजगार की खोज में अपने निर्धारित सरकारी नौकरी पाने के उम्र को भी गंवा देते हैं। उनके समाने बेरोजगारी और भूखमरी की स्थिति बन जाती है। इन घोर संकटों से मुक्ति पाना उनके लिए कठिन हो जाता है। अन्ततोगत्वा वे हार कर रोजगार के लिए अपने राज्य से पलायन कर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, गुजरात जैसे स्थानों पर रोजगार की तलाश में निकल पड़ते हैं। पढ़े–लिखे युवाओं में हीनता की भावना घर करने के कारण अपने यहाँ काम करना तौहीन समझते हैं। ऐसी स्थिति में एकमात्र रास्ता उनके लिए पलायन ही बच पाता है।

बेरोजगारी की स्थिति में व्यक्ति के पास आय स्त्रोत नहीं होने से उसके जीवन में आर्थिक समस्या तो उत्पन्न होती ही है, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक एवं मानसिक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी की स्थिति से निकलने के लिए व्यक्ति कभी–कभी अनैतिक कार्यों तक को करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्र का विकास असंभव हो जाता है। बेरोजगार व्यक्तियों के उपभोग व्यय का स्तर बहुत ही न्यूनतम होता है। उपभोग व्यय के लिए बेरोजगार व्यक्ति अपनी बचत का प्रयोग करते हैं जो कि निश्चित रुप से अल्प काल में ही समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति को परिवर्तित करने का एक ही सरल मार्ग है और वह यह है कि व्यक्तियों को रोजगार प्राप्तक के स्थान पर रोजगार सृजक बनना होगा तभी बेरोजगारी की स्थिति में सुधार संभव हो सकेगा। भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय को निम्नांकित तालिका के माध्यम से प्रकट किया गया है।

तालिका 3: भारत के प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय (रूपये में)[15]

वर्ष	प्रति व्यक्ति औसत मासिक उपभोग व्यय
1974	44.170
1978	68.890
1982	112.310
1988	158.100
1994	281.400
2000	486.160
2006	558.780
2010	927.700
2012	1278.940

*(**Source:** www.ceicdata.com/ National sample Survey Organisation)*

निष्कर्ष

बिहार में बेरोजगारी एक गंभीर समस्या है। यह राज्य और राष्ट्र दोनों के लिए अभिशाप है। रोजगार ने राष्ट्र की श्रम शक्ति को कमजोर कर दिया है। शहरी क्षेत्र में शैक्षाणिक एवं औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है, तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में यह मौसमी बेरोजगारी के रूप में दृष्टिगोचर हो रही है। बेरोजगारी से प्रभावित होकर बिहार सहित नालन्दा जिला के लाखों नौजवान, मजदूर बाहर पालयन कर कम रकम पर अपनी जीविका चलाने को मजबूर है। इसे रोकने के लिए सरकार को पहल करनी पड़ेगी और अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने होगें तभी बेरोजगारी और पलायन पर रोक संभव है।

संदर्भ सूची

1. Chaudhary, D. K. (2001). Unemployment status in Nalanda District of Bihar-A Socio-Economic perspective, Centre for Monitering Indian Economy, Delhi, P 7.
2. Kumar, A., & Kumar, M. (2020) Marginalised Mirgrants and Bihar as an Area of Origin. Kerala Exp, 55, 21.
3. Sabreen, M., & Behera, D. K. (2020). Changing Structure of Rural Employment in Bihar : Issues and Challenges. *The Indian Journal of Labour Economics*, 63(3), 833-845.
4. Chakravorty, B., & Bedi, A. S. (2019). Skills training and employment outcomes in rurual Bihar. *The Indian Journal of Labour Economics*, 62(2), 173-199.
5. Sinha, J.K. Economic impact of unemployment and inflation of output growth in Bihar during 1990-2019. *Statistical Journal of the IAOS*, (Preprint), 1-10.

6. Deshwal, A. (2017). Economic Growth and Poverty Reduction in Bihar During 2004-05 to 2011-12 : Examining the Contradictions. *Avaiable at SSRN* 3009234.

7. Srinivasan, T. N., & Allen, T. (2013). Some Aspects of the Treands in Employment and Unemployment in Bihar and Kerala since the 19705. *Economic Reform in India : Challenges, Prospects and Lessons*, 319.

8. Venkatesh, P. (2013). Recent trends in rural employment and wages in India : has the growth benefitted the agricultural labours? *Agricultural Economics Research Review*, 26(347-2016-17099), 13-20.

9. Kashyap, K. K. D. P. (2005). *Poverty Profile of Bihar : Some Poverty Alleviation in the Third World*, 310.

10. Bhattacharya, B. (2000). *Bihar after bifurcation: A Challenging future, Economic and Political Weekly*, 3800-3804.

11. U.S. Bureau of Labour Statistics (2022). "How the Government Measures Unemployment", Asstal Square Building, Wassington, D.C. 202120001.

12. International Labour Organisation (2013), *Modern Economy,* Vol IIm P 11, Nov 17, 2013

13. एन.एस.ओ. इंपलॉयमेंट एण्ड अनइंपलॉयमेंट सर्वे रिपोर्ट, नीति आयोग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS), NSO, भारत सरकार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय, दिल्ली, 2005.

14. पूर्वोक्त

15. https://www.ceicdata.com/ National sample Survey Organisation, Assess on 05/01/2024.

****